UNEP Emissions Gap Report 2026 — 'The Point of Return'

प्रकाशन तिथि: 22 अक्टूबर 2026

परिचय

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी 17वीं **Emissions Gap Report 2026** — 'The Point of Return' — जारी की। रिपोर्ट का संदेश स्पष्ट है: **1.5°C ताप-सीमा का 'ओवरशूट' (पार कर जाना) अब अनिवार्य है**; प्रश्न यह है कि ओवरशूट कितना ऊँचा और कितना लंबा होगा।

प्रमुख निष्कर्ष (UNEP के अनुसार)

- वर्तमान नीतियों पर विश्व लगभग **2.6°C** वार्मिंग की ओर है।
- 1.5°C की ओर लौटने हेतु वैश्विक उत्सर्जन में कटौती चाहिए: **2030 तक 18%, 2035 तक 45%, 2040 तक 69%** (2025 की तुलना में)।
- परंतु नई राष्ट्रीय योगदान (NDCs) केवल 2030 तक 5-8% और 2035 तक 11-15% कटौती का वादा करती हैं — ज़रूरी स्तर से कहीं कम।
- सबसे कम-ओवरशूट परिदृश्य में भी सदी के मध्य तक तापमान 1.7-1.8°C तक पहुँचेगा, फिर 2100 तक 1.5°C के भीतर लौटने की संभावना लगभग 50% — इसके लिए बड़े पैमाने पर **कार्बन-डाइऑक्साइड हटाना (CDR)** आवश्यक।
- **अवसर:** सौर-पवन ऊर्जा की तेज़ वृद्धि, घटती लागत — प्रौद्योगिकी उपलब्ध, राजनीतिक-वित्तीय इच्छा कम।

संदर्भ और विस्तृत व्याख्या

रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझने के लिए 'उत्सर्जन-अंतर' (emissions gap) की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए: यह अंतर उस कटौती के बीच का है जो 1.5°C पथ के लिए आवश्यक है और जिसका वादा राष्ट्रीय योगदानों (NDCs) में किया गया है। 2026 की रिपोर्ट इस अंतर को आँकड़ों में दिखाती है — ज़रूरी कटौती 2030 तक 18%, 2035 तक 45% और 2040 तक 69% (2025 की तुलना में), जबकि नई NDCs केवल 2030 तक 5-8% और 2035 तक 11-15% की कटौती कहती हैं। यानी अंतर बंद होने के बजाय संरचनात्मक बना हुआ है।

'ओवरशूट' शब्द का अर्थ है लक्ष्य-सीमा को अस्थायी रूप से पार करना; रिपोर्ट का निष्कर्ष कि 1.5°C का ओवरशूट अब अनिवार्य है, इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य समाप्त हो गया — बल्कि बहस अब यह है कि तापमान कितना ऊँचा और कितने दशकों तक ऊपर रहेगा। सबसे अनुकूल परिदृश्य में भी सदी के मध्य तक 1.7-1.8°C और 2100 तक वापसी की संभावना लगभग 50% है, और यह वापसी बड़े पैमाने पर कार्बन-डाइऑक्साइड हटाने (CDR) पर निर्भर है — अर्थात् केवल उत्सर्जन घटाने से काम नहीं चलेगा, वायुमंडल से कार्बन निकालने की तकनीकें भी चाहिए होंगी।

भारत के लिए प्रासंगिकता दोहरी है: प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन कम होने के बावजूद जलवायु-प्रभाव भारी, इसलिए CBDR और वित्त-हस्तांतरण की माँग मज़बूत होती है; साथ ही CBAM जैसे व्यापार-दबाव बढ़ते हैं। रिपोर्ट की आशावादी पंक्ति यह है कि सौर-पवन ऊर्जा की तेज़ वृद्धि और घटती लागत से तकनीकी क्षमता मौजूद है — कमी राजनीतिक और वित्तीय इच्छा की है।

विश्लेषण

- **भारत की स्थिति**: भारत प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन में कम, पर विकासशील-भारी तापमान का प्रमुख प्रभावित; COP-वार्ता में 'सामान्य परंतु विभेदित दायित्व' (CBDR) और वित्त-हस्तांतरण पर भारत का रुख़ इस रिपोर्ट के संदर्भ में और प्रासंगिक।
- **CBAM/वैश्विक व्यापार**: कठोर उत्सर्जन-लक्ष्य यूरोपीय कार्बन-बॉर्डर शुल्क जैसे दबाव बढ़ाते हैं।
- **ओवरशूट का अर्थ**: अस्थायी 1.5°C+ के दौरान ग्लेशियर-क्षय, समुद्र-स्तर, बारिश-पैटर्न पर पहले से बड़ा प्रभाव — अनुकूलन (adaptation) की माँग बढ़ेगी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"UNEP Emissions Gap Report 2026 के अनुसार 1.5°C सीमा का ओवरशूट अनिवार्य हो चुका है। इस निष्कर्ष के वैश्विक और भारतीय निहितार्थों की चर्चा कीजिए और उत्सर्जन-अंतर (emissions gap) पाटने के उपाय सुझाइए।" (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: UNEP की 17वीं Emissions Gap Report 2026 ('The Point of Return') का केंद्रीय निष्कर्ष रखें - 1.5°C ताप-सीमा का ओवरशूट अब अनिवार्य है; 'उत्सर्जन-अंतर' की अवधारणा समझाएँ, यानी आवश्यक कटौती और NDCs के वादों के बीच का फासला।

मुख्य भाग में: रिपोर्ट के आँकड़े रखें - वर्तमान नीतियों पर विश्व लगभग 2.6°C वार्मिंग की ओर; 1.5°C की ओर लौटने हेतु 2025 की तुलना में 2030 तक 18%, 2035 तक 45% और 2040 तक 69% कटौती चाहिए, जबकि नई NDCs केवल 2030 तक 5-8% और 2035 तक 11-15% कहती हैं। बताएँ कि सबसे कम-ओवरशूट परिदृश्य में भी सदी के मध्य तक तापमान 1.7-1.8°C पहुँचेगा और 2100 तक 1.5°C के भीतर लौटने की संभावना लगभग 50% है, जो बड़े पैमाने पर कार्बन-डाइऑक्साइड हटाने (CDR) पर निर्भर है। वैश्विक निहितार्थ (ग्लेशियर-क्षय, समुद्र-स्तर, वर्षा-पैटर्न पर प्रभाव, अनुकूलन की बढ़ती माँग) और भारतीय निहितार्थ (कम प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन के बावजूद भारी जलवायु-प्रभाव, CBDR और वित्त-हस्तांतरण की माँग, CBAM जैसा व्यापार-दबाव) अलग-अलग समझाएँ। उपाय सुझाते समय रिपोर्ट की आशावादी पंक्ति रखें - सौर-पवन ऊर्जा की तेज़ वृद्धि और घटती लागत से प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, कमी राजनीतिक-वित्तीय इच्छा की है।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष निकालें कि ओवरशूट का अनिवार्य होना लक्ष्य की समाप्ति नहीं है - प्रश्न अब ओवरशूट की ऊँचाई और अवधि का है; तीव्र उत्सर्जन-कटौती और CDR का संयोजन ही 1.5°C की ओर लौटने का मार्ग है।

स्रोत

- UNEP Emissions Gap Report 2026 (22 अक्टूबर 2026): https://www.unep.org/en/publications/report/emissions-gap-report-2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी 17वीं Emissions Gap Report 2026 - 'The Point of Return' - जारी की। रिपोर्ट का संदेश स्पष्ट है: 1.5°C ताप-सीमा का 'ओवरशूट' (पार कर जाना) अब अनिवार्य है ; प्रश्न यह है कि ओवरशूट कितना ऊँचा और कितना लंबा होगा।

प्रश्न: UNEP Emissions Gap Report 2026 का केंद्रीय संदेश क्या है?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अपनी 17वीं Emissions Gap Report 2026 - 'The Point of Return' - जारी की। रिपोर्ट का संदेश स्पष्ट है: 1.5°C ताप-सीमा का 'ओवरशूट' (पार कर जाना) अब अनिवार्य है ; प्रश्न यह है कि ओवरशूट कितना ऊँचा और कितना लंबा होगा।

प्रश्न: उत्सर्जन-अंतर क्या है और आवश्यक कटौती के आँकड़े क्या हैं?

रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझने के लिए 'उत्सर्जन-अंतर' (emissions gap) की अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए: यह अंतर उस कटौती के बीच का है जो 1.5°C पथ के लिए आवश्यक है और जिसका वादा राष्ट्रीय योगदानों (NDCs) में किया गया है। 2026 की रिपोर्ट इस अंतर को आँकड़ों में दिखाती है - ज़रूरी कटौती 2030 तक 18%, 2035 तक 45% और 2040 तक 69% (2025 की तुलना में), जबकि नई NDCs केवल 2030 तक 5-8% और 2035 तक 11-15% की कटौती कहती हैं। यानी अंतर बंद होने के बजाय संरचनात्मक बना हुआ है।

प्रश्न: तापमान ओवरशूट का क्या अर्थ है और वापसी किन शर्तों पर निर्भर है?

'ओवरशूट' शब्द का अर्थ है लक्ष्य-सीमा को अस्थायी रूप से पार करना; रिपोर्ट का निष्कर्ष कि 1.5°C का ओवरशूट अब अनिवार्य है, इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य समाप्त हो गया - बल्कि बहस अब यह है कि तापमान कितना ऊँचा और कितने दशकों तक ऊपर रहेगा। सबसे अनुकूल परिदृश्य में भी सदी के मध्य तक 1.7-1.8°C और 2100 तक वापसी की संभावना लगभग 50% है, और यह वापसी बड़े पैमाने पर कार्बन-डाइऑक्साइड हटाने (CDR) पर निर्भर है - अर्थात् केवल उत्सर्जन घटाने से काम नहीं चलेगा, वायुमंडल से कार्बन निकालने की तकनीकें भी चाहिए होंगी।